कैबिनेट के फैसले • बैठक में कुल 46 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई है

7559 पदों पर भर्ती की मंजूरी

▪ नल-जल योजना की मॉनीटरिंग के लिए 700 जेई की बहाली होगी

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

राज्य में 7559 नए पदों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नवसृजित पदों में सर्वाधिक पद उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में सहायकों के हैं। कैबिनेट ने इन नियुक्तियों के लिए वेतन मद में होने वाले खर्चे को भी स्वीकृति दे दी है।

सहायकों के अलावा सांसद-विधायक निधि की योजनाओं व नल-जल योजना की मॉनीटरिंग के लिए 700 जूनियर इंजीनियरों की बहाली होगी। गांव की सड़कों और उन पर बने पुल-पुलियों की देखरेख के लिए असिस्टेंट इंजीनियर, कल्याण छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधकों के अलावा स्वास्थ्य विज्ञान विवि और जल संसाधन विभाग में भी नए पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय में 10 कार्यालय परिचारियों के पदों की भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने 2087 करोड़ की लागत से चार स्टेट हाईवे निर्माण योजनाओं के अलावा आठ साल पूर्व बंद हुई मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को फिर चालू करने पर सहमति जताई। इस योजना को राज्य में लगातार ध्वस्त हुए पुल-पुलियों के बाद शुरू करने पर फैसला हुआ है।

जानिए... कहां किन पदों पर होगी भर्ती

महकमा/ विभाग	पद	संख्या	वेतन खर्च
उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूल	सहायक	6421	127 करोड़
योजना एवं विकास विभाग	कनीय अभियंता	350	13.25 करोड़
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	कनीय अभियंता	350	13.25 करोड़
ग्रामीण कार्य विभाग (संविदा पर)	सहायक अभियंता	231	-----
कल्याण विभाग के छात्रावास	छात्रावास प्रबंधक	91	4.39 करोड़
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी	प्रशासकीय पद	60	-----
जल संसाधन विभाग	प्रशासकीय पद	56	----

2087 करोड़ की लागत से 4 स्टेट हाईवे बनेंगे

कैबिनेट ने 4 स्टेट हाईवे के निर्माण की मंजूरी दी है। इससे सारण, सीवान, बांका, भोजपुर, नालंदा और भागलपुर इलाके में दो लेन चौड़ी सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से इन सड़कों का विकास होगा। चारों हाइवे पर 2087 करोड़ खर्च होगा। कुल 204 किलोमीटर सड़कें 2 लेन चौड़ी होंगी। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि सरकार की मंशा है कि फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार राज्य के हर सुदूर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचे।

स्टेट हाईवे	लंबाई	लागत
छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी	72.18 किमी	701.25 करोड़
2. बनगंगा-जेठियन- बिन्दस	41.25 किमी	361.32 करोड़
3. धौरैया-इंग्लिश मोड़-असरगंज	58.47 किमी	650.50 करोड़
4. आरा-एकौना-खैरा-सहार	32.35 किमी	373.56 करोड़

8 वर्ष बाद फिर से राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना चालू होगी

राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को फिर शुरू करेगी। बीते दिनों दो दर्जन ग्रामीण पुल-पुलियों के क्षतिग्रस्त होने और इनके मेंटेनेंस की समस्या के बाद 8 वर्षों के लंबे अंतराल पर इस योजना को चालू करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि 100 मीटर लंबे पुल-पुलियों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग करेगा। 100 मीटर से अधिक लंबे पुल-पुलियों का निर्माण पुल निर्माण निगम करेगा। निर्माण के लिए पुल-पुलियों का चयन ग्रामीण कार्य विभाग ही करेगा। लंबाई के अनुसार निर्माण की जिम्मेवारी अलग-अलग सौंपी जाएगी। पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में पुल-पुलियों का निर्माण किया जाता था जिसे वर्ष 2016 में बंद कर दिया गया था। सरकार ने उसी योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में अब सड़कों की मरम्मत को भी शामिल कर लिया है।

कमिश्नर 2.50 करोड़ की योजनाओं को देंगे मंजूरी

मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत अब नए सिरे से कमेटी बनेगी और उसे वित्तीय शक्तियां भी मिलेंगी। अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि शहरी विकास योजना के तहत डीएम एक करोड़ तक की योजना स्वीकृत कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त एक करोड़ से ऊपर और 2.50 करोड़ तक की योजना मंजूर करेंगे।

पटना: तीन नए 5 सितारा होटल में मॉल भी खुलेगा

सुल्तान पैलेस के वर्तमान भवन में हेरिटेज होटल और मॉल बनेगा। कैबिनेट ने पटना में 3 नए पांच सितारा होटलों के निर्माण। उनमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की भी स्वीकृति दी है। पटना में पहले ही होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर व सुल्तान पैलेस में 5 सितारा होटलों के निर्माण का निर्णय लिया जा चुका है। -पढ़ें पटना फ्रंट पेज भी

पर्यटन के प्रचार के लिए मार्केटिंग नीति मंजूर

पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग नीति मंजूर हुई है। वैसे पर्यटकीय धरोहर जो सुदूर प्रखंडों और कस्बों में है और अभी तक प्रकाश में नहीं लाए जा सके हैं उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। इस नई नीति के तहत ऐसे स्थलों पर शोधपरक सामग्री के निर्माण के लिए विशेषज्ञ व्यक्ति और संस्था का सहयोग लिया जाएगा।

कैबिनेट के फैसले • किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा, कृषि विभाग के अधीन होगा

ग्रामीण हाटों के विकास के लिए कृषि विपणन निदेशालय का गठन होगा

पॉलिटिकलरिपोर्टर|पटना

कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया जाएगा। यह नया निदेशालय होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इसका उद्देश्य चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 के तहत राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देना, कृषि उत्पाद का भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्द्धन, निर्यात संवर्द्धन और ग्रामीण हाटों का विकास करना है। वहीं, राज्य में निबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-टेलर, बैट्री चालित वाहनों के लिए एकमुश्त पथकर या हरितकर की राशि जमा करने पर दंड से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। दरअसल, ये वाहन विभिन्न कारण से मोटरवाहन कर जमा नहीं कर पा रहे हैं और कर देयता से बाहर हो गए हैं। ऐसे में इनके लिए सरकार ने यह योजना स्वीकृत की है। इसमें उन्हें आंशिक अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से पूरी तरह छूट दी जाएगी। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

कटिहार-बेगूसराय में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल बनेंगे

कटिहार और बेगूसराय में 560-560 बेड वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। कटिहार में वक्फ की भूमि पर उक्त विद्यालय के निर्माण पर 57.18 करोड़ खर्च होंगे। जबकि, बेगूसराय में विद्यालय निर्माण पर 50.61 करोड़ खर्च की मंजूरी दी गई है।

कैंटीन में ग्रुप डी की बहाली तकनीकी सेवा आयोग से : कैंटीन (भोजशाला) में ग्रुप डी के रिक्त पदों पर नियुक्ति अब विभागीय पैनल की जगह बिहार तकनीकी सेवा आयोग से होगी। इसके लिए कैबिनेट ने बिहार सचिवालय भोजशाला परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 को स्वीकृति दी है। भोजशाला के कर्मियों की कार्य प्रकृति अन्य विभागों से भिन्न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डॉक्टर बर्खास्त : मंत्रिमंडल ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी है। इनमें डॉ. चमक लाल बैद्य, डॉ. रवि कुमार चौधरी, डॉ. रोहित कुमार बसाक, डॉ. रविश रंजन, डॉ. शकील जावेद, डॉ. अमित कुमार, डॉ. मसीहूर रहमान शामिल हैं।

कोईलवर मानसिक आरोग्यशाला 321 बेड की होगी

कैबिनेट ने भोजपुर में 272 बेड वाली मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर में अब 321 बेड करने का निर्णय लिया है। पूर्व में इस आरोग्यशाला के निर्माण पर कुल लागत 1.28 अरब रुपए आ रही थी। बेड संख्या बढ़ाने से इसकी लागत 1.97 अरब रुपए हो जाएगी। नालंदा के रहुई में डेंटल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में 404 करोड़ स्वीकृति दी गई थी। इस योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है। अब अनुमानित लागत बढ़कर 597 करोड़ हो गई है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुंगेर के फ्लोराइड प्रभावित खैरा व अन्य टोलों में सहती जल की पाइप से सप्लाई के लिए 40.82 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। मनेर में आर्सेनिक प्रभावित 25 गांवों में पाइप से जलापूर्ति के लिए 1.13 अरब रुपए की योजना स्वीकृत की गई है।

अन्य निर्णय

- दरभंगा एम्स के लिए 37.31 एकड़ जमीन भारत सरकार को मुफ्त में दी जाएगी।
- विधानमंडल सचेतक को उपमंत्री के बदले राज्यमंत्री का दर्जा देने के लिए विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता वेतन एवं भत्ते नियमावली 2006 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत।
- बिहार काराधान विवादों का समाधान अधिनियम 2024 को छह महीने का अवधि विस्तार मिला।
- बिहार मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली 2024 के प्रारूप का अनुमोदन।
- बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 स्वीकृत।
- बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली 2024 स्वीकृत।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 स्वीकृत।
- 15 वर्ष पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16 करोड़ अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

रिसर्च इकोसिस्टम में अवरोधों को पहचान कर दूर करना होगा : पीएम

एएनआरएफ गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक में दिया डैशबोर्ड विकसित करने का सुझाव

कहा- वैश्विक समस्याओं का समाधान भारतीय जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में रिसर्च इकोसिस्टम में बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करना होगा। प्रधानमंत्री आवास पर मंगलवार को आयोजित नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने डैशबोर्ड विकसित करने का भी सुझाव दिया। इस डैशबोर्ड से देश में हो रहे अनुसंधान एवं विकास से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।

एनआरएफ का उद्देश्य उद्योग, शिक्षा, और सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करना और वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के साथ ही उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी और योगदान के लिए तालमेल का तंत्र तैयार करना है। पीएम ने कहा कि शोध मौजूदा समस्याओं के नए समाधान खोजने पर केंद्रित होना चाहिए। समस्याएं वैश्विक हो सकती हैं लेकिन उनका समाधान भारतीय जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत के वैज्ञानिक समुदाय के लिए नया अध्याय शुरू हुआ है। भारत सरकार अनुसंधान को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम शैक्षणिक अनुसंधान और उद्योग के बीच अधिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेंगे।

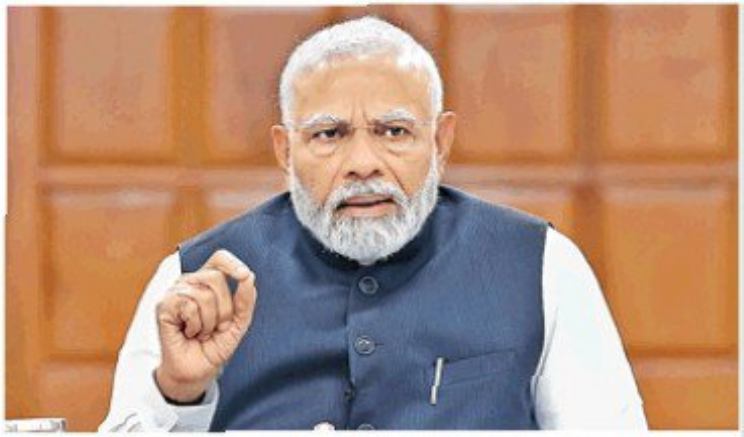

नई दिल्ली में एएनआरएफ की बैठक के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी। एएनआइ

सेवानिवृत्त विज्ञानियों और प्रोफेसरों को मेंटर के तौर पर नियुक्त करने की तैयारी

उच्च शिक्षा संस्थानों की शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार निचली रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों में शीर्ष संस्थानों के सेवानिवृत्त विज्ञानियों और प्रोफेसरों को मेंटर के रूप में नियुक्त करने की तैयारी रही है। आइआइटी जैसे शीर्ष संस्थानों के विज्ञानियों और प्रोफेसर मेंटर के तौर पर मार्गदर्शन देंगे। पार्टनरशिप फार एक्सेलेरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च (पीएआइआर) को लांच करने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत शीर्ष स्तर के अनुसंधान संस्थानों को उन संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा जहां अनुसंधान क्षमता सीमित है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि बड़े लक्ष्य तय करने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने विशेषज्ञता के आधार पर विशेषज्ञों की सूची तैयार करने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने अनुसंधान और नवाचार के लिए संसाधनों की वैज्ञानिक निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिक समुदाय को विश्वास होना चाहिए कि उनके प्रयासों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी।

अटल टिंकरिंग लैब्स की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि इन लैब्स की ग्रेडिंग की जा सकती है। एएनआरएफ ने इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर सेल, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, कृषि जैसे कई क्षेत्रों में अनुसंधान शुरू करने का निर्णय लिया है। गवर्निंग बाडी ने यह भी कहा एएनआरएफ रणनीतियों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

Developed India needs civil governance reforms

Institutional flexibility and autonomy is needed to bolster school/health centre/*anganwadi*-level excellence HT ARCHIVE

These will facilitate greater inclusion, without which the vision of Viksit Bharat by 2047 will be hard to realise

Amarjeet Sinha

A developed India by 2047 is impossible without an inclusive India, where every citizen gets opportunities to develop to their fullest capability. The country not only needs double-digit growth to raise its per capita income, but it also needs to secure the demographic dividend through better human capital. With half the population set to live in urban locations in the next ten years, urban governance for the poor needs a transformation in city planning and regulation.

There are several areas where civil governance must make a difference, from the income of the bottom quintiles to health and nutrition, from educational attainment and skilling to green growth. It must secure the well-being of the urban poor and improve the State-citizen interface to contribute to ease of living and doing business. Communities will have to play a critical role in developing accountability at all levels.

By general consensus, India's failure to ensure quality universal delivery of public goods like education, health, nutrition, clean environment, and urban living spaces compromises its quest for an inclusive society and economy, with concomitant fallout for productivity and wages that can lead to lives of dignity. Civil governance has to reorganise itself on the basis of evidence from below, on what works and what does not. Here are some considerations to be kept in mind as we go about restructuring civil governance.

First, decentralised community action under the leadership of *gram panchayats* and urban local bodies, with funds, functions, and functionaries, monitored by women's collectives, is the best way forward. Need-based provision of professionals along with flexible untied grants and adequacy of public resources is non-negotiable. Convergence has to be a bottom-up process, through decentralised community action and planning for the 29 sectors in rural and 18 in urban that are in the 11th and the 12th Schedules of the Constitution.

Second, there is a need to make standard setting, city-wide planning, social and financial auditing, transparency in the selection of professionals, and their incremental development through capacity development central to civil governance reforms. A functional right to public service, with timelines and guaranteed compliance, will complement this through community action under well-defined partnership agreements. The institutionalisation of all such partnerships and concomitant responsibilities is needed for effectiveness.

Third, there is evidence that education, health, skills, nutrition, livelihoods, and employment are best delivered through convergence as the gains in each of these sectors have consequences for other sectors. The gram/urban *basti sabhas* need to be monitored to ensure the participation of every line-department functionary. Civil society organisations should ensure the social participation of vulnerable social groups. The use of Local Government Directory Code (LGD Code) in urban and rural areas allows real-time public information on geography-wise performance. The more we subject data to public scrutiny, the better the outcomes for governance.

Fourth, the Sustainable Development Goals (SDGs) framework can become a metric for desired governance outcomes. The Mission Antyodaya Survey (MAS) of every *gram panchayat*, since 2017, has already localised the SDGs in 206 data points. A similar process is needed at the urban *basti*/ward level to enable the identification of gaps and deficits. Mission Antyodaya data is validated by the *gram sabha* and duly verified by elected *panchayat* leaders and women's collectives. This ensures high credibility.

Fifth, innovations in human resource engagement are a must. Besides the induction of professionals, due weightage should be given to incrementally developing local residents as community teachers, nurses, and creche workers, as local residency does matter in accountability. There is also a very strong case for longer tenures for development functionaries in *gram panchayats*/urban local bodies as well as block, district, and state offices. Transformation in human development sectors takes time, and there is a role for the continuity of people, policies, and programmes. In human development, outcomes can only be measured over five to seven years. So, transfer policies need to be revisited. There is also a very strong case for performance assessment of frontline workers — school teachers, auxiliary nurse midwives, *anganwadi* workers, and others. Performance-based incentives for the effectiveness of schools, skill centres, *anganwadis*, and health and wellness centres need to be considered.

Sixth, institutional flexibility and autonomy is needed to bolster school/health centre/*anganwadi*-level excellence. Third-party assessments have to be institutionalised to monitor this. Zero tolerance for mediocrity in capacity development institutions has to become the basis for innovations for outcomes.

Seventh, local, state, and national governments must partner for civil governance outcomes. Central and state funding in the sectors falling in the local government's domain must necessarily be spent with the approval of local governments, after validation through the decentralised, community-led planning process.

Eighth, emphasis must be given to evidence-based selection of beneficiaries of government programmes, with objectively verifiable indicators. The Socio-Economic Census 2011 was one such effort. Its adoption across programmes such as Ujjwala, Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Saubhagya, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) helped create the *labharthi varg* (beneficiary class) of the deprived across region, religion, caste and creed. Technology must be effectively leveraged for transparent identification and updating of beneficiary lists.

Ninth, civil and technical services must be guided by evidence rather than the pressures and pulls of democracy. Evidence-based action and outcome-based governance are what the higher civil and technical services ought to provide.

The achievement of outcomes is only possible with conviction-driven leadership across levels that are driven by hard evidence. That alone will secure an India for all, an inclusive and developed India.

Amarjeet Sinha is a retired civil servant. The views expressed are personal

Vietnam storm death toll climbs to 127; 764 injured

Typhoon Yagi struck on Saturday bringing winds in excess of 149 kilometres per hour and flooding not seen in decades

Agencies
letters@hindustantimes.com

Flood triggered by Typhoon Yagi submerges houses in Bac Giang province, Vietnam, on Sunday. AP

HANOI: Typhoon Yagi and the landslides and floods it triggered have killed at least 127 people, and 54 others are missing in northern Vietnam, the disaster management agency said on Tuesday.

Most of the victims were killed in landslides and flash floods, the agency said in a report. Nearly 764 people have been injured, it added.

Yagi struck on Saturday bringing winds in excess of 149 kilometres per hour and a deluge of rain that has caused flooding not seen in decades, according to locals.

More than 59,000 people have been forced to evacuate their homes in Yen Bai province, local authorities said on Tuesday, after the floodwaters engulfed almost 18,000 homes.

Floodwaters in Hanoi have reached levels not seen since 2008, state media reported, citing a senior local official, and forecasters have warned more is expected in the city's historic centre.

Phan Thi Tuyet, 50, who lives close to the swollen and fast-moving Red River which runs through the capital, said she had never experienced such high water.

"I have lost everything, all gone," she told AFP, clutching her two dogs as she was evacuated by boat, along with other residents whose homes were flooded.

"I had to come to higher ground to save our lives. We could not bring any of the furniture with us. Everything is under water now."

Typhoons in the region are forming closer to the coast, intensifying more rapidly, and staying over land longer due to climate change, according to a study published in July.

Yagi downed bridges, tore roofs off buildings, damaged factories and triggered widespread flooding and landslides, leaving 64 people still missing.

Hanoi authorities said more than 25,000 trees in the city had been uprooted in the storm. Huge trunks blocked key roads in the city centre, creating large traffic jams.

The north of the country — densely populated and a major manufacturing hub for global tech firms including Samsung — was badly hit, with floodwaters in the city of Yen Bai at record levels, meteorologists said. Authorities have issued flood and landslide warnings for 401 communes across 18 northern provinces.

One-storey homes in parts of Thai Nguyen and Yen Bai cities were almost completely submerged in the early hours of Tuesday, with residents waiting on the roofs for help.

Rescuers were trying to reach residential areas to retrieve old people and children. On social media, relatives of those stuck in floodwater posted desperate pleas for help and supplies in the early hours of the morning.

Crops including bananas, guavas and corn — which are usually sold in nearby markets — were all flooded.

As well as the dead and missing, flooding and landslides have also injured at least 764 people, officials at the ministry of agriculture said on Tuesday.

Authorities stopped heavy vehicles crossing a major bridge over the Red River in central Hanoi on Tuesday and suspended a train line across Long Bien bridge as the water level rose.

The action followed the dramatic collapse of a bridge higher up the river in northern Phu Tho province on Monday.

Pictures showed half of the 375-metre Phong Chau bridge gone.

Curfews, web curbs in Manipur amid clashes

Thomas Ngangom and Prawesh Lama
letters@hindustantimes.com

Police fire teargas shells to disperse protesters in Imphal on Tuesday. AFP

IMPHAL: Internet services were on Tuesday snapped in five districts of Manipur and strict prohibitory orders were imposed in three districts as protesters as security forces clashed across the strife-torn state, where violence has ratcheted up and shattered the fragile calm over the past 10 days.

Data services, including cellular and broadband, will be cut off in five districts till Saturday, the state home department said in an order, even as the administrations of Imphal East, Imphal West and Thoubal imposed indefinite curfews after agitations in the districts turned violent.

The law-and-order downturn also prompted the state government to order schools and colleges to stay shut till Thursday.

Thousands of students took part in agitations throughout Manipur, with much of the protests focussed in the capital Imphal, where 40 people were injured when they faced-off with security forces while marching towards Raj Bhavan, demanding the dismissal of the director general of police and security adviser over the recent spate of drone and missile attacks.

Police officers pinned the violence on misinformation, and said the protesters pelted them with stones and marble balls, forcing them to fire tear gas and charge the crowds. Protesters, however, said they threw stones because police "injured peaceful protesters" and stopped them from meeting the governor.

"Some miscreants on social media circulated fake news that a woman protester died in firing during the protest... The violence was also exacerbated by another piece of fake news that a student was killed. We later came to know that a protester, possibly a student, fell off the flyover. He was injured," said an officer of the Rapid Action Force (RAF).

Clashes in the conflict-ridden state have dialled up significantly this month, with militants turning to modern weaponry like drones and rockets, adding a fresh layer of violence to the ongoing use of rifles and grenades.

Ten people have died since September 1, of whom one was killed in a drone attack and another by a rocket. A former army soldier was also stabbed and beaten to death.

The Centre has formed a committee of top officers from the police, army and paramilitary forces to examine the use of explosive-bearing drones. The committee is now preparing a

continued on →6

Russia an essential part of talks on Ukraine conflict: Jaishankar

Rezaul H Laskar
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: India believes that Russia's participation is essential to take forward any negotiations aimed at ending the Ukraine conflict, and New Delhi is open to any serious step towards peace, external affairs minister S Jaishankar said on Tuesday.

Jaishankar made the remarks while addressing a media briefing in Berlin following talks with his German counterpart Annalena Baerbock during which the Russia-Ukraine conflict was extensively discussed. The comments also came against the backdrop of a renewed push for peace talks and speculation about a possible role for India in bringing the warring countries to the negotiating table.

Referring to Prime Minister Narendra Modi's meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on the margins of the G7 Summit in Italy in June, and his visits to Moscow and Ukraine in the past two months, Jaishankar said the Indian premier long discussions with both President Vladimir Putin and Zelensky.

India's position, he said, is based on some postulates – one, that differences and disputes cannot be settled through war; two, that a solution won't emerge from the battlefield, and that negotiations are the "only way forward". He added: "At some point, there has to be a negotiation. When there is a discussion, we also think it is essential to have Russia in it, otherwise the discussions don't gain further movement."

External affairs minister S Jaishankar with his German counterpart Annalena Baerbock in Berlin on Tuesday. S JAISHANKAR-X

Jaishankar sidestepped questions on whether India will take up Zelensky's proposal for hosting the second peace summit on Ukraine and only said that New Delhi will back any serious move ending the conflict. "Suggestions have been made [about India hosting the peace summit] from time to time but let me say this – for us, this is not about a process or about being seen to do something. What is important for us is the reality of the conflict that is taking place today. So, we are always open to any step that is serious, that is impactful and that is, in our view, a step towards peace," he said.

India participated in a series of preparatory meetings ahead of the first peace summit on Ukraine that was hosted by Switzerland in June. India sent a senior diplomat to that summit but didn't join the joint communique "for a variety of reasons", Jaishankar said.

He noted that India has also been involved in several specific initiatives related to the Ukraine conflict, such as the opening of a corridor last year for the export of grains from Ukraine and matters related to the security of the Zaporizhzhia nuclear power station.

"Where India is concerned, it's up to what the two parties [Russia and Ukraine] want. We continuously talk to them," he said, pointing out that National Security Adviser Ajit Doval is currently visiting Russia.

Participating in a discussion with Baerbock at the German foreign ministry ahead of their formal talks, Jaishankar also said India could not set the terms for negotiations but could offer advice to Russia and Ukraine. "It's not for us to tell you what terms [for talks]. If you want advice, we are always willing to give it. That's really the position that we've taken," he said.

At the media briefing, Baerbock described Modi's visit to Ukraine in August as an "important signal", and said any Indian backing for Zelensky's 10-point peace plan would have Germany's "full support". She also noted that India has "channels to Russia" due to the long-standing relations between the two countries.

Russia was invited to be part of the peace summit process but its government said it wasn't not considering attending such meetings without Ukraine ceding various territories, she said.

"This shows the Russian government still has the goal it had on Feb 24, 2022 – they want to destroy Ukraine [and] for them, it's not about negotiations," she added, speaking in German.

Germany asked to ease export controls to boost bilateral ties

NEW DELHI: Germany should update its export control regime to foster greater defence cooperation with India and look at ways to ramp up bilateral trade and investments, external affairs minister S Jaishankar told a gathering of German ambassadors in Berlin on Tuesday.

Jaishankar, who is in Germany on the second leg of a three-nation tour, called for enhanced cooperation in innovation and technology, especially AI, fintech and green technologies, and for close consultation between the two countries on global issues.

At the annual ambassadors' conference, Jaishankar sought enhanced defence cooperation, especially as India's private sector expands in this area. "It will require export controls updating as well. We welcome the recent air exercises between India and Germany and await the impending ship visits to Goa."

Noting that India is a nearly $4 trillion economy with 8% growth prospects for decades, Jaishankar said changes in the country and an easier business climate should motivate greater trade and investment. "Our trade, currently at $33 billion, and mutual investment levels can surely do better," he said. **REZAUL H LASKAR**